बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 220 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 02 सितम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण ट्रेन परिचालन में देरी

नई दिल्ली । दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर सोमवार दोपहर सिग्नलिंग में गड़बड़ी आ गई, जिससे ट्रेनों के परिचालन में देरी हुई। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''टर्मिनल स्टेशन मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम में सिग्नलिंग समस्या के कारण समयपुर बादली की ओर जाने के लिए ट्रेनों को वापस मोड़ने में थोड़ा अतिरिक्त समय लग रहा है।'' सुल्तानपुर और मिलेनियम सिटी सेंटर के बीच रेल यातायात प्रभावित हुआ है। शुक्रवार सुबह भी येलो लाइन पर इसी तरह की गड़बड़ी के कारण देरी की खबरें आई थीं। डीएमआरसी ने कहा कि सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं और जल्द ही सुचारू संचालन बहाल हो जाएगा।

वोट चोरी पर छोड़ेंगे हाइड्रोजन बम, चेहरा नहीं दिखा पाएंगे पीएम : राहुल

पटना ।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को भाजपा को एक आसन्न खुलासे की चेतावनी देते हुए कहा कि वह जल्द ही वोट चोरी के अपने आरोपों पर एक हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे, क्योंकि महादेवपुरा के बारे में जो दिखाया गया वह सिर्फ़ एक परमाणु बम था। मतदाता अधिकार यात्रा के अंतिम दिन एक सभा को संबोधित करते हुए, गांधी ने भाजपा पर तीखे हमले करते हुए कहा कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाली ताकतें अब भारत के संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं। महाराष्ट्र में हमसे चुनाव चोरी किया गया था। तकरीबन एक करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद जोड़े जाते हैं। जितना हमें लोकसभा में मिला, उतना विधानसभा में गया। नए सारे वोट भाजपा के खाते में चले गए। क्योंकि, चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर वोट चोरी की। हमने साफ दिखाया कि एक क्षेत्र में एक लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। हमने डाटा के साथ दिखाया। चुनाव आयोग हमें वोटर लिस्ट नहीं देती। सीसीटीवी नहीं दिखाती। चार महीने, 16-17 घंटे काम कर हमने देश के सामने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी, लोकतंत्र की चोरी, युवाओं के भविष्य की चोरी। यह आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड लेकर अडाणी-अंबानी को दे देंगे। महात्मा गांधी की हत्या करने वाली शक्ति संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन्हें संविधान की हत्या नहीं करने देंगे। हमने बिहार की यात्रा की। बिहार के सारे के सारे युवा खड़े हो गए। छोटे-छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, गद्दी छोड़। बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखाते थे। आपने एटम बम का नाम सुना है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। पूरे देश को आपकी सचाई पता लगने वाली है। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा देश को नहीं दिखा सकेंगे।

मल्लिकार्जुन खरगे बोले- सतर्क नहीं रहे तो मोदी-शाह डुबो देंगे

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संबोधित करते हुए कहा कि इस 15 दिन की यात्रा पूरे देश में चर्चा चली। भाजपा ने इसमें रुकावट डालने की पूरी कोशिश की। गठबंधन के लोग राहुल जी या तेजस्वी जी नहीं

डरे। वोट चोरी करने वाले पैसा चोरी करने की भी आदत रखते हैं। बैंक से चोरी कर बाहर जाने वालों को भी यह संभालते हैं। मोदी जी बिहार में वोट चोरी कराकर जीतना चाहते हैं। सतर्क नहीं रहेंगे तो यह मोदी और शाह आपको डुबा देंगे। आजादी के बाद जो वोट का अधिकार दिलाया गया, उसे खोना नहीं। यह महात्मा गांधी, आंबेडकर और नेहरु जी ने अधिकार दिया है। सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए खरगे ने कहा कि यह आरएसएस वाले आपको कचरा में जाकर फेंकेंगे। खरगे ने पुलिस को राहुल गांधी की यात्रा रोकने के लिए भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने नारा लगवाया- मोदी को हटाओ।

तेजस्वी यादव बोले- भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए डुलीकेट नीतीश

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे के बाद हेमंत सोरेन अभिवादन करते हुए अपना संबोधन शुरू किया और मुकेश सहनी और क्रिकेटर युसुफ पठान को बड़ा भाई कहकर संबोधित किया। आदाब, प्रणाम और सलाम करते हुए तेजस्वी ने कहा कि यह बिहार की धरती है, लोकतंत्र की जननी है। यह कुछ, कुछ भी नहीं दो भाजपाई लोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर लोकतंत्र की धरती से लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं। लोकतंत्र चाहिए या राजतंत्र चाहिए? यह लोग चाहते हैं कि बिहारी लोग को ठग लें। फैक्टरी लगाएंगे गुजरात में और वोट चाहिए बिहार में! हमारे मुख्यमंत्री इतनी बार पलटी मारे हैं कि इनका दिमाग चकरा गया है। एक इंजन अपराध और एक भ्रष्टाचार में लगा है। अपना वोट कटने नहीं देना है। बड़ी चालाकी से फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं। इस सरकार को आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकना है। भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं सीएम नीतीश कुमार। मंत्रीजी के यहां सुबह शाम जाते हैं। और, उनके विभाग के इंजीनियर पकड़े जाते हैं तो रुपए जला दिए जाते हैं। करोड़ों-अरबों जला दिए जा रहे हैं। यह नकलची सरकार है। हम जो कहते हैं, वह यह करने लगती है। यह सरकार नकल तो कर सकती है, विजन नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे-आगे और यह सरकार पीछे-पीछे। डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजनल सीएम चाहिए। अभी तो डुप्लीकेट सीएम का राज चल रहा है। हमलोग एफआईआर वगैरह से डरने वाले नहीं हैं। लालू प्रसाद की औलाद हैं। कृष्ण के वंशज हैं, जिनका जन्म ही जेल में हुआ था। लालूजी का खून तेजस्वी के अंदर है। मोदीजी झूठ बोलने की फैक्टरी हैं। इंडस्ट्री हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होल सेलर हैं। वोट की चोरी करने वालों को उखाड़ फेंकना है।

सोरेन बोले- वोट चोरी करने वाले पकड़े गए, आज पर्दाफाश कर रहे

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह चुनाव बिहार नहीं, देश को बचाने का अवसर है। षड्यंत्रकारियों के खिलाफ बड़ा आंदोलन करना है। इन्होंने मुझे भी जेल में डाल दिया था। बिहार की ऐतिहासिक धरती से आग्रह है कि जिस तरह से वोटर रिवीजन का काम किया है, लेकिन यह विशेष और गहन-दोनों को जोड़कर पुनरीक्षण कराया गया है और यह गलत है। साजिश है। आज यह वोट चोरी करने वाले पकड़े गए हैं। आज हम इसका पर्दाफाश कर रहे हैं। ईडी-सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करने वाले चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं।

बीजेपी-कांग्रेस ने मिलकर अरविंद केजरीवाल को हराने की साजिश रची, आतिशी ने साधा निशाना

(वेबवार्ता)

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक चौंकाने वाला दावा किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को अब साफ समझ आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराने की साजिश रच रहे थे. आतिशी ने अपने पोस्ट में लिखा कि ये कोई आरोप नहीं, बल्कि खुद दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष का कबूलनामा है. दोनों पार्टियां ऊपर से लड़ाई का दिखावा करती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे दोस्ती निभाती हैं. दिल्ली की जनता अब सच जान चुकी है बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर केजरीवाल जी को हराने की साजिश रची थी। ये कोई आरोप नहीं बल्कि खुद दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष का कुबूलनामा है। दोनों पार्टियाँ ऊपर से लड़ाई का दिखावा करती हैं लेकिन पर्दे के पीछे दोस्ती निभाती हैं। आतिशी का कहना है कि दिल्ली की राजनीति में जो टकराव दिखाई देता है, वह केवल जनता को भ्रमित करने के लिए है. वास्तव में कांग्रेस और बीजेपी मिलकर आप की सरकार को कमजोर करने और केजरीवाल को सत्ता से हटाने की कोशिश में जुटी हैं. आतिशी ने अपने ट्वीट में दिल्ली के मतदाताओं को सतर्क रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि जनता सावधान रहे, ये लड़ाई अब जनता बनाम बीजेपी-कांग्रेस की मिलीभगत की है. उन्होंने दावा किया कि यह लड़ाई केवल एक पार्टी या नेता की नहीं, बल्कि दिल्ली की जनता की इज्ज़त और उनके वोट की ताकत की है. बता दें कि हाल ही में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा था. केजरीवाल ने कहा था कि आप के बड़े नेताओं को जेल में डाला गया लेकिन गांधी परिवार का एक भी नेता जेल नहीं गया.

दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश, हुआ दिन में अंधेरा; नोएडा-गाजियाबाद में ऐसा है मौसम का हाल

नई दिल्ली । (वेबवार्ता) दिल्ली समेत एनसीआर में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। दोपहर दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। जिसकी वजह से मौसम सुहाना हो गया है। इसके साथ ही रोशनी कम होने से दिन में ही अंधेरा छा गया। वहीं सुबह के वक्त नोएडा और गाजियाबाद में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. सोमवार को दोपहर एकदम से मंदिर मार्ग पर तेज बारिश हुई। जहां अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कामकाजी लोगों के लिए पहुंचना थोड़ा मुश्किल भरा रहा। वहीं बारिश स्कूल की छुट्टी के दौरान बच्चों के लिए भी परेशानी का सबब बनी। मौसम विभाग के अनुसार, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब पर बना है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों पर भी इस वेदर सिस्टम का असर नजर आ सकता है। दिल्ली में अगस्त में मौसम ने हर मामले में नए- नए रिकॉर्ड बनाए हैं। चाहे वर्षा हो या औसत अधिकतम-न्यूनतम तापमान। इसलिए यह माह 13 साल में सबसे ठंडा भी रहा है। इस साल राजधानी में 2010 के बाद से अगस्त की सर्वाधिक वर्षा हुई है। रविवार शाम तक 480.81 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो अगस्त 2010 में दर्ज 455.1 के बाद सबसे यादा है। यानी 15 वर्षों में सबसे यादा वर्षा। अगस्त में वर्षा का ऑल टाइम रिकॉर्ड 583.3 मिमी का है, जो 1961 में दर्ज किया गया था। इस साल अगस्त में 14 दिन वर्षा हुई है। अच्छी वर्षा के कारण ही औसत मासिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से नीचे रहे हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि इस अगस्त में दिल्ली का औसत अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री रिकार्ड किया गया है, जो 2012 में दर्ज 33.1 डिग्री के बाद 13 साल में सबसे कम है।

अर्थव्यवस्था को लेकर अतार्किक उत्साह, ट्रंप के टैरिफ का झटका अभी नहीं दिखा: कांग्रेस

नई दिल्ली । कांग्रेस ने सोमवार को अप्रैल-जून 2025 के जीडीपी के आंकड़ों को लेकर सरकार की आलोचना की और कहा कि इनसे 'अतार्किक उत्साह पैदा हुआ है और इनमें अभी तो 'ट्रंप का टैरिफ का झटका दिखाई नहीं दे रहा है जिसके असल परिणाम दूसरी तिमाही में दिखाई देने लगेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि टैरिफ से बचने के लिए निर्यातकों ने पहले से ही अमेरिका को अतिरिक्त निर्यात (फ्रंट लोडिंग) कर दिया था, जिससे निर्यात वृद्धि और जीडीपी के मुख्य आंकड़ों में वृद्धि हुई है। रमेश ने 'एक्स पर कहा, ''अप्रैल-जून 2025 की अवधि के जीडीपी आंकड़े अतार्किक उत्साह का कारण बने हैं, लेकिन इनमें कुछ स्पष्ट विरोधाभास भी हैं जिन पर एक जानेमाने बैंक की रिपोर्ट ने सवाल उठाए हैं और जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया, ''शहरी खपत अब भी काफी

कमजोर है और ग्रामीण खपत संरचनात्मक बाधाओं का सामना कर रही है। रमेश ने कहा कि नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर (यानी मुद्रास्फीति को समायोजित किए बिना) अब भी धीमी है और वास्तव में, जनवरी-मार्च 2025 तिमाही की तुलना में काफी कम है। उन्होंने कहा, ''उपभोग, निवेश और व्यापार जीडीपी वृद्धि के मुख्य निर्धारक हैं। लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से तिमाही वृद्धि दर का पूरा 1.8 प्रतिशत अंक इन तीन निर्धारकों से नहीं समझाया जा सकता। यह विसंगति बहुत बड़ी है और इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। रमेश ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में बिक्री वृद्धि, मुनाफे की वृद्धि के विपरीत, लगातार धीमी हो रही है। कांग्रेस नेता ने कहा, ''ट्रंप टैरिफ का झटका इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में दिखाई नहीं देता। दरअसल टैरिफ से बचने के लिए निर्यातकों ने पहले से ही अमेरिका को अतिरिक्त निर्यात (फ्रंट लोडिंग) कर दिया था, जिससे निर्यात वृद्धि और जीडीपी के मुख्य आंकड़ों में वृद्धि हुई है। रमेश ने कहा कि टैरिफ के वास्तविक प्रभाव निश्चित रूप से दूसरी तिमाही से दिखने शुरू हो जाएंगे।

भारत की अर्थव्यवस्था अप्रैल-जून में अपेक्षा से अधिक 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो पांच तिमाहियों में सबसे तेज़ गति की थी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाए, जिससे कपड़ा जैसे प्रमुख निर्यातों के लिए खतरा पैदा हो रहा है। शुक्रवार को जारी नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन से प्रेरित थी, तथा व्यापार, होटल, वित्तीय और रियल एस्टेट जैसी सेवाओं से भी इसमें मदद मिली।

दिल्ली की सड़कों पर 36 साल बाद लौटेंगी डबल डेकर बसें, अब दिखेगा इलेक्ट्रिक स्वरूप

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली की सड़कों पर 36 साल बाद डबल डेकर बसों की वापसी होगी। 1989 में पुराने बेड़े की जर्जर हालत और सीएनजी युग की शुरुआत के चलते इन्हें बंद कर दिया गया था। अब दिल्ली सरकार इन्हें इलेक्ट्रिक स्वरूप में दोबारा चलाने की तैयारी में है। इसके लिए बसों का ट्रायल रन चुनिंदा रूट पर जल्द शुरू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के लिए अशोक लेलैंड ने डीटीसी को सीएसआर फंड से एक इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस दी है, जिसे ओखला डिपो में खड़ा किया गया है। बस की ऊंचाई 4.75 मीटर और लंबाई 9.8 मीटर है। इसमें 63 से अधिक यात्री एक साथ सफर कर सकते हैं। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दो और बसें जल्द मिलने की उम्मीद है। पूर्व उपायुक्त (परिवहन विभाग) अनिल छिकारा का कहना है कि डबल डेकर बस की वापसी तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों से निपटने के बाद ही संभव होगी। यह पहल दिल्लीवासियों को सुनहरे दिनों से जोड़ेगी। ट्रायल के दौरान बैटरी की परफॉर्मेंस, रूट पर सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा का आकलन किया जाएगा। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। फ्लाईओवर की ऊंचाई, सड़कों पर लटकी पेड़ों की टहनियां और ओवरहेड बिजली की तारें इन बसों के संचालन में बाधा बन सकती हैं। इसके लिए डीटीसी अधिकारी रूट मैपिंग कर रहे हैं ताकि सुरक्षित मार्ग तय किया जा सके। राजधानी में डबल डेकर बसों का संचालन 1949 में डीटीसी के अधीन शुरू हुआ था। पीले, हरे और लाल रंग की ये बसें दिल्ली की शान हुआ करती थीं। भीड़भाड़ वाले इलाकों जैसे कश्मीरी गेट, पुरानी दिल्ली, करोल बाग और कनॉट प्लेस तक पहुंचने के लिए लोग अक्सर इन्हीं बसों को चुनते थे। यात्रियों के लिए ऊपरी डेक से दिल्ली की गलियों और बाजारों का नजारा अविस्मरणीय अनुभव होता था। दिल्ली सरकार का दावा है कि इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसों की वापसी पर्यावरण हितैषी और जनता के अनुकूल कदम है।

दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट! हथिनीकुंड से पानी छोड़ने के बाद यमुना खतरे के निशान पर

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है। सोमवार सुबह हथिनीकुंड बैराज से 29,313 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जाने की आशंका है। अधिकारियों को निचले इलाकों में गश्त के साथ-साथ कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि चूंकि ओआरबी (दिल्ली ओल्ड रेलवे ब्रिज) का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है और 206.50 मीटर से अधिक होने की संभावना है, इसलिए जल्द ही केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की एक सलाह जारी होने की उम्मीद है। इसलिए, सभी सेक्टर अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखें और संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक कार्रवाई करें, जैसे कि नदी के तटबंधों के भीतर रहने वाले लोगों को चेतावनी दी जाए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए,- दिल्ली सरकार के एक आदेश में कहा गया है। बयान में कहा गया है कि पुलिस और वन एवं वन भूमि संरक्षण विभाग के कर्मचारी दाएं और बाएं सीमांत तटबंधों पर गश्त करेंगे और आवश्यकतानुसार संवेदनशील बिंदुओं, नियामकों/पंपों आदि पर चौबीसों घंटे निगरानी रखेंगे। गुरुवार को दिल्ली के मयूर विहार में बाढ़ राहत शिविर स्थापित किया गया, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर पिछले दिन खतरे के निशान को पार कर गया था। मयूर विहार निवासी अशोक ने इन बाढ़ राहत शिविरों के बारे में एएनआई को बताया, -ये तंबू नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए लगाए गए हैं; बाढ़ आने पर वे बाहर आकर इन तंबुओं में रहेंगे।- इस बीच, आईएमडी ने रविवार को कहा कि भारत ने अगस्त 2025 के दौरान दशकों में अपनी सबसे अधिक वर्षा दर्ज की है, जिसमें कई राज्यों में असाधारण वर्षा हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने ज़ोर देकर कहा कि महीने के उत्तरार्ध में मानसून की गतिविधि फिर से ज़ोरदार हो गई है और सामान्य से अधिक वर्षा के साथ सितंबर तक जारी रहने की उम्मीद है।

आईएमडी महानिदेशक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, -अगस्त महीने में पूरे भारत में 268.1 मिमी बारिश हुई, जो 2001 के बाद से सातवीं सबसे ज्यादा और 1901 के बाद से 45वीं रैंक है। अगस्त महीने में उत्तर-पश्चिम भारत में 265.0 मिमी बारिश हुई, जो 2001 के बाद से सबसे ज्यादा और 1901 के बाद से 13वीं रैंक है। दक्षिण भारत में 250.6 मिमी बारिश हुई, जो 2001 के बाद से तीसरे सबसे ज्यादा और 1901 के बाद से आठवीं सबसे ज्यादा है।

विश्लेषण : ट्रंप के टैरिफ़ से विश्व सकल मांग में कमी होगी

प्रभात पटनायक

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ पर मीडिया में चलताऊ ढंग से, उनके खास संदर्भ के हिसाब से ही, चर्चा हो रही है। यह वह संदर्भ है जहां अमेरिकी सरकार, बढ़े हुए टैरिफ से आने वाला राजस्व मालों तथा सेवाओं की खरीदी पर खर्च करने के प्रति अनिच्छुक है, जिस मामले को हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरे देश भी, जो कि ट्रंप के बढ़े हुए टैरिफ के चलते अमेरिकी बाजार खो रहे होंगे, इस घाटे की भरपाई अपने ही घरेलू बाजारों का विस्तार करने के जरिए करने में असमर्थ होंगे। उनके घरेलू बाजारों में इस तरह की बढ़ोतरी सरकारी खर्चों में बढ़ोतरी किए जाने के जरिए ही हो सकती है, लेकिन यह भी तब तक असंभव होगा, जब तक कि व्यवस्था या तो राजकोषीय घाटे के जरिए की जाए या फिर अमीरों पर कर लगाने के जरिए की जाए। लेकिन, ये दोनों ही रास्ते वैश्वीकृत वित्तीय पूंजी के लिए जैसे अभिशाप ही हैं और वर्तमान नवउदारवादी व्यवस्था में राज्य को इस वित्तीय पूंजी का हुक्म मानना ही होता है। इसलिए, अमेरिकी संरक्षणवाद के साथ कुल मिलाकर विश्व की समग्र मांग का सिकुड़ना और इसलिए नव-उदारवादी पूंजीवाद के संकट का और तीखा होना तय हुआ है। इस पहलू पर बहुत कम ही ध्यान दिया गया है कि ट्रंप के टैरिफ से भले ही अमेरिका में घरेलू उत्पाद तथा वहां रोजगार में बढ़ोतरी हो जाए, इससे विश्व पूंजीवादी संकट बदतर ही होने जा रहा है और इसलिए, अमेरिका तथा अन्य देशों, दोनों को मिलाकर, उत्पाद का स्तर घटने ही जा रहा है। आइए, हम देखें कि विश्व सकल मांग में यह कमी किस तरह होती है। टैरिफ से घरेलू बाजार में मुद्रा मजदूरी के सापेक्ष आयातित मालों की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह कम से कम आर्थिक रूप से, इस तरह के आयातों की जगह घरेलू तौर पर उत्पादित मालों द्वारा लिया जाना संभव बनाता है। टैरिफ जाहिर है कि सारे आयातों को खत्म नहीं करते हैं, लेकिन मान कर चलें कि वह कुछ तो खत्म कर ही देते हैं। जो आयात इन टैरिफ के बावजूद बने रहते हैं, उन पर सरकार टैरिफ राजस्व बटोरती है, जो उपभोक्ताओं की जेब से आता है, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा मेहनतकशों का होता है, जिनसे टैरिफ के चलते बढ़ी हुई कीमतों के जरिए वसूली की जाती है। दूसरे शब्दों में, टैरिफ जिस हद तक आयातों को पूरी तरह से खत्म करने में कामयाब नहीं होते हैं और इसलिए उनसे किसी हद तक टैरिफ राजस्व की उगाही संभव होती है, उसके जरिए, मजदूर वर्ग के हाथों से निकल कर सरकार के हाथों में, क्रय शक्ति का पुनर्वितरण हो रहा होता है। चूंकि मेहनतकश जनता अपनी लगभग पूरी की पूरी क्रय शक्ति मालों तथा सेवाओं को खरीदने पर खर्च करती है, उसकी जेब से निकलकर, सरकार के खजाने की दिशा में क्रय शक्ति का इस तरह का कोई भी पुनर्वितरण, टैरिफ लगाने वाले देश में सकल मांग के स्तर में कमी नहीं कर रहा होगा, बशर्ते उसकी सरकार टैरिफ का यह राजस्व मालों व सेवाओं की खरीदी पर खर्च कर रही हो। लेकिन, अगर वह सरकार ऐसा नहीं करती है, तो टैरिफ लगाने वाले देश में सकल मांग के स्तर में कमी हो जाएगी। अमेरिका में ठीक यही होने जा रहा है क्योंकि ट्रंप के टैरिफ से आने वाले राजस्व को मालों तथा सेवाओं की खरीद पर खर्च नहीं किया जाने वाला है। ट्रंप प्रशासन, अमीरों को भारी कर रियायतें देता आया है और टैरिफ से आने वाले राजस्व का उपयोग इस तरह की कर रियायतों से पैदा होने वाले राजकोषीय घाटे में कमी करने के लिए किया जाएगा। दूसरे शब्दों में टैरिफ राजस्व खर्च तो किया ही नहीं जाएगा बल्कि उसे तो राजकोषीय घाटे को घटाने में भी लगाया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि सरकार द्वारा बटोरा जाने वाला टैरिफ राजस्व का ठीक उतना, अमेरिका में सकल मांग के स्तर को घटा रहा होगा। और चूंकि शेष दुनिया की सरकारों का खर्च, अमेरिकी मांग में इस कमी की भरपाई करने के लिए बढ़ नहीं रहा होगा, इसका अर्थ यह हुआ कि पूरी दुनिया को मिलाकर देखा जाए तो, सकल मांग का स्तर घट रहा होगा, जो विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी के हालात को और बिगाड़ देगा। बहरहाल, खुद अमेरिका में, सकल मांग में कमी के बावजूद, आयातों की कीमत पर घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरे शब्दों में, टैरिफ के चलते अमेरिका में तो मंदी दूर हो सकती है, लेकिन समग्रता में पूंजीवादी दुनिया को देखा जाए तो यानी अमेरिका और बाकी दुनिया को जोड़कर देखा जाए तो, आर्थिक गतिविधि के स्तर में गिरावट हो जाएगी। यह अमेरिका द्वारा अपने यहां से ''बेरोजगारी का निर्यात'' किए जाने से ज्यादा का मामला है यानी यह सिर्फ अमेरिका द्वारा ''पड़ोसी जाए भाड़ में'' की नीति अपनाए जाने भर का मामला नहीं है। यह ऐसा मामला है जहां अगर मालों पर टैरिफ लगाए जाने के चलते अमेरिका में घरेलू उत्पाद में 100 इकाई की बढ़ोतरी होती है तो, शेष दुनिया में उत्पाद में सिर्फ 100 इकाई की नहीं बल्कि 100 से ज्यादा इकाई, मिसाल के तौर पर 120 या 150 इकाई की कमी हो रही होगी। इससे समग्रता में दुनिया के स्तर पर उत्पाद के स्तर में गिरावट आ रही होगी। संक्षेप में यह ऐसा मामला है जहां समग्रता में दुनिया के स्तर पर आर्थिक गतिविधि का स्तर तो सिकुड़ रहा होगा, जबकि अमेरिका में आर्थिक गतिविधि का स्तर बढ़ रहा होगा।

दूसरे देश अगर अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगा देते हैं, तो उससे इस स्थिति में रत्तीभर फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। वास्तव में जिस हद तक ये देश अपने टैरिफ राजस्व का, जो कि अपने घरेलू मजदूरों की कीमत पर जुटाया जा रहा होगा, अपने राजकोषीय घाटों को कम करने के लिए या अपने धनवानों को कर रियायतें देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि धनवान तो अपने हाथ आए संसाधनों में से एक छोटे से हिस्से का ही उपभोग करते हैं, इसका समग्र प्रभाव सकल विश्व मांग के और भी ज्यादा सिकुड़ जाने के रूप में सामने आएगा। दूसरे शब्दों में, अमेरिकी टैरिफ के जवाब में अन्य देशों द्वारा ऐसा ही किया जाना, मांग को तथा इसलिए, उत्पाद को भी अमेरिका में इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में वापस लाने का काम तो जरूर करेगा, लेकिन यह समग्रता में विश्व अर्थव्यवस्था के हालात को और बदतर ही बनाएगा और नव-उदारवादी पूंजीवाद का संकट और बढ़ जाएगा। टैरिफ पर होने वाली आम चर्चा में, यह आखिरी नुक्ता पूरी तरह से छूट जाता है। इस तरह की चर्चा में टैरिफ को किसी भी देश द्वारा सिर्फ मांग का तथा इसलिए उत्पाद का, अन्य देशों से हटाकर अपने देश की ओर, तबादला करने के साधन के रूप में ही देखा जाता है। लेकिन, अगर टैरिफ ऐसे हालात में थोपे जा रहे हों, जहां टैरिफ राजस्व, जो मेहनतकश जनता की कीमत पर बटोरा जाता है, सरकार द्वारा खर्च किया ही नहीं जाता है तथा उसको बचतों को बढ़ाने के ही काम में आता है, तब टैरिफ का समग्रता में दुनिया में मांग तथा उत्पाद के स्तर को सिकोड़ने में अतिरिक्त प्रभाव पड़ेगा यानी नवउदारवादी पूंजीवाद का संकट और उलझ जाएगा। इस संकट के संदर्भ में अमेरिका की भूमिका खासतौर पर दर्ज करने लायक है।

उदारवादी पूंजीवादी रुख के अनुसार, पूंजीवादी दुनिया का नेता होने के नाते, उससे यह उम्मीद की जाती थी कि इस संकट पर काबू पाने के लिए, विकसित पूंजीवादी देशों की ओर से एक एकजुट रणनीति तय करने का नेतृत्व करेगा। उदारवादी पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों ने यही सुझाया होता। वास्तव में, 1930 की महामंदी के दौरान जॉन केन्स ने विकसित पूंजीवादी देशों की ओर से ऐसी सम्मिलित कार्रवाई का ही सुझाव दिया था। इसके विपरीत आज हो यह रहा है कि अमेरिका अकेले खुद को ही संकट से निकालने की कोशिश कर रहा है और समग्रता में पूंजीवादी दुनिया के लिए चीजों को और भी बदतर बना रहा है।

दूसरे शब्दों में अमेरिका जो ''मेक अमेरिका ग्रेट अगेन'' करना चाहता है, समग्रता में पूंजीवादी दुनिया के इस संकट से उबरने के लिए कोई रास्ता सुझाने का नेतृत्व करने के जरिए नहीं करना चाहता है, बल्कि शेष दुनिया को और खासतौर पर विकासशील दुनिया के देशों को, और ज्यादा बदहाली मंजूर करने के लिए मजबूर करने के लिए, उनकी बांह मरोड़ने के जरिए ऐसा करना चाहता है, जिससे अमेरिका अकेले ही इस संकट से खुद को निकालने में कामयाब हो सके। ट्रंप जब ऐसा कर रहा है, तो वह ऐसा कोई इसलिए नहीं कर रहा है कि वह शैतान है या मूर्ख है और इस वजह से संकट से उबरने का जो ''जागरूक'' तरीका है, उससे वह परहेज कर रहा है। वह ऐसा इसलिए कर रहा है कि वह जो कुछ भी कर रहा है, उदारवादी पूंजीवादी बुद्धिजीवी जिस तरह की सुंदर स्थिति की कल्पना करते हैं उसके बरक्स, यही पूंजीवाद की प्रकृति के साथ मेल खाता है। चूंकि पूंजीवाद एक नियोजित व्यवस्था नहीं है, वह अपने सामने उपस्थित संकट के किसी ''तार्किक समाधान'' के अनुकूल नहीं होता है। इसलिए, अमेरिका इस संकट के बीच अपने ही स्वार्थों की हिफाजत करने की कोशिश कर रहा है।

सम्पादकीय...

दोमुहा सांप चीन

आज जिस प्रकार से आर्थिक वैश्वीकरण ने दुनिया का स्वरूप बदल दिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा मनमाने टैरिफ लगाए जाने के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उनको देखते हुए भारत और चीन की नजदीकियों को वक्त का तकाजा ही कहा जाएगा। आज के दौर में अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर न तो कोई स्थायी शत्रु होता है और न ही कोई स्थायी मित्र होता है। यह बात सच है कि आजादी के बाद से भारत की मित्रता सोवियत संघ से रही और पाकिस्तान की अमेरिका से। पंडित जवाहर लाल नेहरू के शासनकाल में भारत-चीन संबंधों की शुरूआत काफी मधुर हुई थी। तब हिन्दी-चीनी भाई-भाई के नारे लगे थे लेकिन 1962 के चीनी आक्रमण ने दोनों देशों के संबंधों में ऐसी कड़वाहट भर दी कि आज तक भारत को 1962 का युद्ध प्रेत की तरह चिपटा हुआ है। यह बात सच है कि किसी भी संवेदनशील देश को अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए, परन्तु यह बात भी उतनी ही सत्य है कि युग के साथ-साथ युग का धर्म भी बदल जाता है। इस वर्ष की अब तक की सबसे बड़ी मुलाकात पर देशवासियों की नजरें लगी हुई थीं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की महामुलाकात हुई। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब ट्रम्प के टैरिफ वॉर और उनकी कारोबार वाली धमकियों का सामना भारत और चीन दोनों ही देश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग दोनों ने दोनों देशों के साथ आने की जरूरत को समझा और दोनों ही देश सहयोग को तैयार हुए। दरअसल अमेरिका ने ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी हैं कि भारत और चीन का करीब आना आवश्यक हो चुका है। ट्रम्प की दादागिरी के खिलाफ नए इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर की शुरूआत हो सकती है। दो पड़ोसी और विश्व के सबसे बड़ी आबादी वाले भारत और चीन स्थिर और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा समृद्धि पर साकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। बहुध्रुवीय विश्व के लिए यह सकारात्मक संकेत है। भारत और चीन के संबंध भरोसे की कसौटी पर परखे जाते रहे हैं। चीन की घुसपैठ, अरुणाचल पर उसके दावे, पूर्वी लद्दाख सीमा पर लम्बे चले गतिरोध, गलवान घाटी में हुए संघर्ष और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन द्वारा पाकिस्तान की मदद करने और कुछ अन्य कारणों से भरोसा लगातार टूटता रहा है लेकिन टैरिफ वॉर के बाद ऐसे संदेश आ रहे थे कि चीन भारत के करीब आना चाह रहा है। मार्च 2025 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक गोपनीय पत्र भेजा था, जिसमें लिखा गया था कि भारत और अमेरिका के बीच कोई भी समझौता हुआ तो उससे चीन को नुक्सान हो सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस पत्र के बाद भारत और चीन के रिश्तों के अर्थ बदल गए। इससे पहले मोदी और शी जिनपिंग 2024 में रूस के कजान और 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में मिले थे। दोनों बार फोरम ब्रिक्स समिट का था। कुछ दिन पहले ही चीनी विदेश मंत्री वांग यी सीमा मामलों के विशेष प्रतिनिधियों की 24वीं बैठक में शामिल होने भारत दौरे पर आए थे। उनकी मुलाकात यहां पीएम मोदी से हुई। इससे पहले वो एनएसए डोभाल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी मिले थे। तब भी चीन की तरफ से दोस्ती की नई डगर पर चलने के संकेत मिलने लगे थे। चीन को मालूम है कि अगर वो ग्लोबल साउथ में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। दुनिया के कारोबार में अमेरिका को टक्कर देना चाहता है, तो फिर उसे भारत जैसे पड़ोसी को साथ लेना ही होगा। बिना भारत के वो अपने कारोबार को उस मुकाम पर नहीं पहुंचा पाएगा जहां कि वो हसरत पाले हुए है लेकिन सच ये भी है कि कारोबार के साथ क्षेत्रीय संतुलन भी जरूरी है। भारत को भी इस समय अपने ट्रेड की चिंता है। दोनों देशों ने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में सीमा पर शांति बनाए रखना, बॉर्डर ट्रेड को फिर से खोलना और सीधी उड़ान सेवाओं को शुरू करना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी की एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी। इस सम्मेलन में रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गीस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस भी भाग ले रहे हैं। एससीओ सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों में विश्व की कुल आबादी का लगभग 43 प्रतिशत हिस्सा रहता है। व्यावहारिक दृष्टि से भारत-रूस-चीन त्रिकोण के अलावा यह सभी देश एकजुट हो जाएं तो अमेरिका के ट्रम्प किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। भारत की चिंताएं पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर भी हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान चीन का उपनिवेश बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान ने चीन के हथियारों और सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल किया। भारत पाकिस्तान और चीन की मित्रता को तोड़ने का प्रयास नहीं करेगा लेकिन चीन को भारत की चिंताओं पर ध्यान देना होगा। कितना अच्छा हो कि बीती ताहि बिसार दे यानि अतीत को भुलाकर भारत-चीन सीमा विवाद को हल कर लें और चीन भारत की भौगोलिक सीमाओं का सम्मान करे। जहां तक व्यापार का सवाल है चीन को भी अपना बाजार भारत के लिए खोलना होगा। भारत-चीन व्यापार घाटा बढ़कर 99.2 अरब डॉलर तक पहुंचना चिंताजनक है। चीन अब लगभग हर औद्योगिक श्रेणी में भारत के आयात पर हावी है। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से आपसी सम्मान और आपसी हितों के आधार पर दोनों देशों को बढ़ना होगा। कुल मिलाकर मोदी और जिनपिंग ने ट्रम्प को बड़ा संदेश दे दिया है। अब तो अमेरिका के कई नेता और विशेषज्ञ यह महसूस कर रहे हैं कि ट्रम्प ने भारत को छेड़कर एशिया में अपना एक मजबूत साझीदार खो दिया है।

विवाह समारोह-पवित्र संस्कार, आधुनिकता का दंश और समाज की चुनौती

भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में शादी केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि एक पवित्र संस्कार मानी जाती है। वेदों से लेकर पुराणों तक, गृहस्थ जीवन को धर्म का महत्वपूर्ण आधार बताया गया है। विवाह को केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों और दो कुलों का मिलन माना जाता है। इसीलिए इसे सात फेरे, सातपदी मंत्र, कन्यादान, होम, आशीर्वाद और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सम्पन्न कराया जाता है। किंतु आज बदलते समय में विवाह के स्वरूप में गहरा बदलाव दिखाई दे रहा है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र मानता हूं कि शादी समारोह,जो कभी अध्यात्म, त्याग, संस्कार और सामाजिक सामंजस्य का प्रतीक था,अब धीरे-धीरे दिखावे, पैसे की होड़, दहेज, शराब और भव्यता की दौड़ में सिमटता जा रहा है। यह बदलाव न केवल भारतीय संस्कृति के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सामने एक विकृत परंपरा स्थापित कर रहा है। इस विषय का विस्तार से डिस्कशन व विश्लेषण हम 5 प्वाइंटों के आधार पर करेंगे। साथियों बात अगर हम विवाह एक पवित्र संस्कार आध्यात्मिक और सामाजिक आयाम की करें तो,भारतीय संस्कृति में विवाह को सोलह संस्कारों में एक प्रमुख संस्कार माना गया है। यह केवल पति-पत्नी के शारीरिक या भावनात्मक संबंध का बंधन नहीं है, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधना का आधार है। विवाह का उद्देश्य केवल जीवनसाथी चुनना नहीं,बल्कि समाज में संतुलित,संस्कारित और धार्मिक जीवन की स्थापना करना है। सात फेरे, जिन्हें हर दंपति विवाह के समय अग्नि के साक्षी में लेता है, केवल शब्द नहीं हैं बल्कि जीवन के लिए आजीवन वचन हैं।आज की पीढ़ी इन मंत्रों और वचनों की गहराई को समझे बिना केवल विवाह को सोशल इवेंट की तरह देखने लगी है। होटल, रिजॉर्ट, फार्महाउस और डेस्टिनेशन वेडिंग ने विवाह को पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी के बजाय लक्जरी इवेंट में बदल दिया है। यह बदलाव भारतीय समाज की मूल आत्मा के विपरीत है। साथियों बात अगर हम आधुनिकता का दंश और बदलती शादी की परंपरा व दहेज और उपभोक्तावादी संस्कृति की करें तो आधुनिकता अपने साथ तकनीकी विकास,वैश्विक संपर्क और नए अवसर लाती है, परंतु इसका अंधानुकरण विवाह जैसे संस्कारों को विकृत कर रहा है। आज शादियाँ अधिकतर स्टेटस सिंबल बन गई हैं।(अ) लाखों- करोड़ों रुपए खर्च कर शाही शादी दिखाना अब फैशन बन चुका है। (ब) शादी समारोहों में शराब, डीजे, नाइट पार्टी और वेस्टर्न कल्चर की नकल आम हो गई है। (क) रिश्तेदारों और मेहमानों का सम्मान अब मेन्यू की विविधता और सजावट की भव्यता से आंका जाने लगा है, न कि आत्मीयता और आदर से।इस भौतिकवादी दृष्टिकोण ने विवाह की पवित्रता को गहरे तक प्रभावित किया है। जहां कभी विवाह का अर्थ दो आत्माओं का आध्यात्मिक बंधन था, वहीं आज विवाह का अर्थ सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और वीडियो बन गया है।दहेज और उपभोक्तावादी संस्कृति-विवाह का कुरूप चेहरा -दहेज प्रथा भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक है। स्वतंत्रता के बाद से लगातार प्रयासों के बावजूद यह कुरीति खत्म नहीं हुई। आधुनिकता और भौतिकतावाद ने इसे और मजबूत कर दिया है। आज शादी समारोह में गाड़ियों की डिमांड, महंगे गिफ्ट्स, कैश और प्रॉपर्टी की अपेक्षा खुलेआम की जाती है।दहेज न केवल विवाह के पवित्र बंधन को कलंकित करता है बल्कि यह महिलाओं के लिए अपमानजनक और अमानवीय स्थिति पैदा करता है। हजारों बेटियाँ आज भी दहेज के बोझ के कारण या तो शादी नहीं कर पातीं या शादी के बाद उत्पीड़न का शिकार होती हैं। साथियों बात अगर हम विवाह और शराब संस्कृति, के तेजी से बढ़ते प्रचलन की करें तो, भारतीय समाज में विवाह हमेशा से संयम, मर्यादा और उत्सव का संगम रहा है। परंतु पिछले दो दशकों में शादियों में शराब की संस्कृति तेजी से फैली है। यह न केवल समारोह की गरिमा को कम करता है बल्कि कई बार हिंसा, विवाद और दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है।आज समाज के सामने यह प्रश्न है कि क्या विवाह का उत्सव बिना शराब, नाच-गाने और दिखावे के संभव नहीं? विवाह जैसे पवित्र अवसर पर यदि आत्मसंयम और मर्यादा खो जाए तो वह केवल मनोरंजन बनकर रह जाता है। साथियों बात अगर हम विवाह में बढ़ता दिखावापन और समाज पर असर की करें तो,शादी में कितना खर्च हुआ? यह प्रश्न आज समाज का सबसे बड़ा मूल्यांकन बन गया है। किसी परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा अब शादी की भव्यता से तय होती है। परिणामस्वरूप गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार कर्ज, उधार और आर्थिक बोझ तले दब जाते हैं।

(अ) शादियों में करोड़ों का खर्च करना प्रेस्टीज इश्यू बन चुका है। (ब) आम परिवार इस दौड़ में शामिल होने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई खर्च कर देते हैं। (क) और छोटे कस्बों में भी यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, जिससे आर्थिक असमानता और बढ़ रही है।यह प्रवृत्ति भारतीय समाज के लिए खतरनाक है क्योंकि इससे सामाजिक संतुलन और समानता की अवधारणा को गहरी चोट पहुंचती है। साथियों बात अगर हम घटते पारंपरिक संस्कार और अनुष्ठान की करें तो पहले विवाह घर-आंगन में, मंदिरों या पंचायतों में पूरे परिवार और समाज की सहभागिता से होते थे। बारात में ढोल-नगाड़े, लोकगीत,नृत्य, भजन- कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान का विशेष महत्व होता था। परंतु अब इनकी जगह डीजे, फिल्मी गाने और कोरियोग्राफ्ड डांस ने ले ली है।कन्यादान, होम, सप्तपदी, वरमाला जैसे संस्कार केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं।कई बार डेस्टिनेशनवेडिंग्स में पुरोहित और मंत्रोच्चार तक फास्ट फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। यह बदलाव कहीं न कहीं विवाह को केवल मनोरंजन का साधन बना रहा है। साथियों बात अगर हम समाज को दिशा दिखाने कीआवश्यकता व सादगीपूर्ण विवाह की करें तो,आज समय की मांग है कि समाज इस बदलते परिदृश्य पर गंभीर चिंतन करे। विवाह को पुनः उसके मूल स्वरूप में लाने की आवश्यकता है। इसके लिए(अ)धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को विवाह संस्कारों की पवित्रता का प्रचार करना चाहिए। (ब) परिवारों को बच्चों को बचपन से ही विवाह संस्कारों की महत्ता सिखानी चाहिए।(क) सरकार को दहेज और अनावश्यक खर्च पर रोक लगाने वाले कानूनों को कड़ाई से लागू करना चाहिए। (ड)समाज में सादगीपूर्ण विवाह को प्रोत्साहित करने वाले अभियान चलाने चाहिए। सादगीपूर्ण विवाह—भविष्य की राहआज कई राज्यों में सामूहिक विवाह और सादगीपूर्ण विवाह की परंपरा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें खर्च सीमित रखा जाता है और धार्मिक अनुष्ठानों को महत्व दिया जाता है। इससे न केवल आर्थिक बोझ कम होता है, बल्कि विवाह की सामाजिक और आध्यात्मिक महत्ता भी बनी रहती है।सादगीपूर्ण विवाह को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाना होगा। जब तक दिखावे और भव्यता को प्रेस्टीज माना जाएगा, तब तक यह प्रवृत्ति नहीं रुकेगी। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि विवाह भारतीय संस्कृति का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण संस्कार है। इसे आधुनिकता और दिखावे की भेंट चढ़ाना हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय होगा। समाज को यह समझना होगा कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का पवित्र मिलन है, जिसका उद्देश्य धर्म, परंपरा और संस्कारों को आगे बढ़ाना है। यदि हम विवाह को पुनः उसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप में स्थापित कर पाते हैं, तभी हम आधुनिकता के दंश से बचकर आने वाली पीढ़ियों को एक सशक्त और संस्कारित समाज दे पाएंगे।

ट्रंप टैरिफ चुनौती के बीच अर्थव्यवस्था की ताकत बनता कृषि क्षेत्र

ट्रंप के टैरिफ वार के दौरान ही 2025 वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी के परिणाम इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाते है कि ट्रंप द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था करार देने के बावजूद चीन से भी हमारी जीडीपी विकास दर अधिक रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी 7.8 प्रतिशत रही है। यह पिछले एक साल यानी कि अप्रैल-जून 2024, जुलाई-सितंबर 2024, अक्टूबर-दिसंबर 2024 और जनवरी-मार्च 2025 की तुलना में भी अधिक है। सबसे खासबात यह है कि जीडीपी में बढ़ोतरी का श्रेय कृषि और सर्विस सेक्टर को जा रहा है। कृषि सेक्टर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह अर्थ व्यवस्था का प्रमुख स्तंभ है और तेजी से विकसित होती भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। निश्चित रुप से इसका श्रेय अन्नदाता को तो जाता ही है इसके साथ ही सरकार की किसानोन्मुखी और कृषिनोन्मुखी नीति को भी जाता है। कृषि और संबंध क्षेत्र जिसमें कृषि के साथ ही पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन शामिल है। एक मोटे अनुमान के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का 14 प्रतिशत योगदान है तो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुप से 50 प्रतिशत से अधिक लोगों की आजीविका एग्रीकल्चर सेक्टर पर आज भी निर्भर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को पूरा करने में कृषि क्षेत्र में भी पीछे नहीं रहने वाला है। देश में करीब 51 प्रतिशत यानी कि 159 मिलियन हेक्टेयर भूमि में खेती हो रही है। इसमें से 50 प्रतिशत से कुछ अधिक भूमि ही सिंचित है जबकि बड़ा क्षेत्र मानसून की मेहरबानी पर निर्भर है। यह एक सकारात्मकता है कि इस साल अभी तक मानसूनी बरसात औसत से अधिक और अच्छी बरसात हुई है। पिछले सालों में भी मानसून अनुकूल रहने से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। कृषि और अन्नदाता की महत्ता को कोरोना काल ने बेहतर तरीके से समझा दिया है। कोरोना काल में कृषि सेक्टर ने दो तरह से सहभागिता निभाई। एक तो जहां सब कुछ लॉक डाउन की भेंट चढ़ रहा था यहां तक कि घर में कैद होकर रह गए थे तब भी कृषि सेक्टर अपनी प्रभावी भूमिका निभाता रहा वहीं दूसरी और अन्नदाता की मेहनत से देश के गोदामों में भरे खाद्यान्नों के भण्डारों ने देश में खाद्यान्न की उपलब्धता बनाये रखी। आज भी करीब 80 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। यह अपने आप में बड़ी बात है।

योजनाबद्ध तरीके से एक और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे है वहीं खासतौर से दलहन-तिलहन में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी है। किसान सम्मान निधि किसानों के लिए बड़ा सहारा बनती जा रही है वहीं ब्याजमुक्त कृषि ऋण, केसीसी का बढ़ता दायरा और ई नाम मण्डी, प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा, स्टोरेज सुविधा बढ़ने के साथ ही समय पर खाद-बीज आदि की उपलब्धता का प्रभाव सामने है। एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र की जीडीपी में भागीदारी 3.7 प्रतिशत रही है जबकि साल भर पहले यह 1.5 थी। ऐसे में यह अपने आप में आशा का संचार है। निर्यात के क्षेत्र में भी कृषि सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दरअसल अमेरिका और ट्रंप का निशाना हमारा कृषि क्षेत्र और डेयरी क्षेत्र प्रमुखता से है। अमेरिका के आगे सरेण्डर होने के स्थान पर हमारी सरकार ने ट्रंप के टैरिफ से निपटने का संकल्प लिया है यह अपने आप में बड़ी बात है। हो सकता है कि आने वाली तिमाही में ट्रंप टैरिफ का असर दिखाई दे पर जिस तरह से सरकार द्वारा वैकल्पिक प्रयास आरंभ किये जा रहे है उससे लगता है कि अर्थ व्यवस्था पर नकारात्मक असर नहीं होगा या होगा भी तो देश इससे निपटने को तैयार है। 50 प्रतिशत टैरिफ की चुनौती को आज समूचा देश निपटने को तैयार है। हालांकि ट्रंप ने सोचा था कि हम सरेण्डर कर देंगे, झुक जाएंगे पर अब गीदड़ भभकी बेअसर होती देखकर ट्रंप की खीज अवश्य बढ़ने लगी है। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप को अपने देश में ही अपनी तुगलकी नीति के कारण देर सबेर मुंह की खानी पड़ेगी। हालांकि अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ निर्णय को अनुचित करार दे दिया है। आने वाले दिनों में इसके प्रभाव अमेरिका में और अधिक दिखाई देंगे क्योंकि हम और हमारी सरकार ट्रंप की चुनौती से निपटने के लिए मानसिक रुप से तैयार हो चुकी है। खैर यह विषयांतर होगा। कहने का अर्थ है कि यह और आने वाले साल भी खेती-किसानी के लिए सकारात्मक ही होंगी। रबी के अच्छे परिणाम आये है। चालू खरीफ में अच्छे मानसून के चलते अच्छी बुवाई हुई है। बुवाई क्षेत्र बढ़ा है। सरकार भी बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि यह कटु सत्य है कि ग्रामीण रहवासियों की आजीविका का प्रमुख माध्यम खेती ही है तो समूचे देश की खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इसी क्षेत्र के पास है। अमेरिकी नीति के कारण निर्यात पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को भी अन्य देशों को निर्यात बढ़ाकर पूर्ति करने की बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही खेती किसानी की अपनी चुनौतियां बरकरार है। आज भी कुल कृषि उत्पादन का 10 से 15 प्रतिशत उत्पादन फसलोत्तर सुविधाओं की कमी के कारण बर्बाद हो जाता है। कृषि जोत कम होती जा रही है। बढ़ते शहरीकरण का प्रभाव भी पड़ रहा है। कृषि क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज, परिवहन की कोल्ड चेन और भण्डारण की बेहतर व्यवस्थाओं की दरकार है। कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र और फूड पार्क जिस तरह से आकार लेने चाहिए थे वे ले नहीं पाये है। बीमा क्षेत्र में भी बहुत किया जाना अपेक्षित है तो कृषि उपज की खरीद व्यवस्था और एमएसपी खरीद को लेकर भी तेजी से काम किया जाना है।

और शहीद की मां की प्रतिमा भी नहीं लग पाई

जब तक उस वृद्धा की हड्डियों में जान रही वह जंगल से लकड़ियां बीनती रही और उनसे मिले चार पैसों से आटा, दाल, चावल जुटाती रही। जब इतनी भी शक्ति शेष नहीं बची तो उसने कभी ज्वार, कभी बाजरे का घोल पीकर गुजारा काट लिया, मगर कभी किसी से मांग कर नहीं खाया। उसकी यह स्थिति स्वाधीनता प्राप्ति के बाद बरसों तक जारी रही मगर उन्हीं दिनों उसे तलाश करता करता, उसके बेटे का एक दोस्त आया और उसे देखकर नम आंखों से अपने झांसी स्थित घर ले गया। उसका अपना घर भी टूटा-फूटा था और बहुत छोटा था, मगर अपने दिवंगत दोस्त को वचन दिया था कि उसकी मां की देखभाल स्वयं करेगा, इसलिए विपरीत हालात में भी उस वृद्धा मां को अपने जर्जर घर में ले आया। जब लगा कि एक कमरे के अपने जर्जर घर में वृद्धा की सेवा नहीं हो पाएगी तो वह उसे सीहोर में अपने एक मित्र के घर छोड़ आया जहां कुछ वर्षों बाद बुढ़िया ने अंतिम सांस ली। बुढ़िया का नाम था जगरानी देवी। पांच बेटों की मां थी। पांचवें व अंतिम बेटे का नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। जगरानी देवी उसे प्यार से चंदू कह कर बुलाती थी। आज़ाद के उस साथी, जो उसे लेकर झांसी आ गया था, का नाम था सदाशिव और सीहोर में अंतिम क्षणों में उसकी देखभाल का दायित्व संभालने वाले का नाम था भगवान दास। सदाशिव व भगवान दास भी जवानी में 'आजाद' के साथी हुआ करते थे। महानायक चंद्रशेखर आजाद तो याद है मगर वृद्ध मां को हम भूल गए। आज़ाद की प्रतिमाएं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश व पंजाब-हरियाणा में लगभग सभी प्रमुख नगरों में लगी हैं। वृद्धा जगरानी की शवयात्रा में जब कुछ लोगों के सामने उसके अंतिम दिनों के संघर्ष की बातें चर्चा में आई तो जोश में आकर कुछ युवाओं ने उसका एक स्मृतिस्थल बनाने का निर्णय लिया। मूर्ति बनाने का कार्य चंद्रशेखर आज़ाद के खास सहयोगी कुशल शिल्पकार रुद्र नारायण सिंह को सौंपा गया। उसने फोटो को देखकर आज़ाद की माताश्री के चेहरे की प्रतिमा तैयार कर दी। जब केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकारों को यह पता चला कि आज़ाद की मां की मूर्ति तैयार की जा चुकी है और सदाशिव राव, रूपनारायण, भगवानदास माहौर समेत कई क्रांतिकारी झांसी की जनता के सहयोग से मूर्ति को स्थापित करने जा रहे है तो इन सरकारों ने अमर बलिदानी शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद की माताश्री की मूर्ति की स्थापना को देश, समाज व झांसी की कानून व्यवस्था के लिए खतरा घोषित कर उनकी मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम को प्रतिबंधित कर पूरे झांसी शहर में कर्फ्यू लगा दिया। चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई, ताकि अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की माता की मूर्ति की स्थापना न की जा सके। मगर जनता का एक क्षुब्ध वर्ग आजाद की माता की प्रतिमा लगाने के लिए निकल पड़ा। अपने आदेश की झांसी की सड़कों पर बुरी तरह धज्जियां उड़ते देख तिलमिलाई तत्कालीन सरकारों ने पुलिस को गोली का आदेश दे डाला। आजाद की माताश्री की प्रतिमा को अपने सिर पर रखकर पीठ की तरफ बढ़ रहे सदाशिव को जनता ने चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार घाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साय पैंचशीला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार घाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होगी। (DELHIN/2017/0082)

बारिश में तालाब बनीं स्मार्ट सिटी की सड़कें

मुरादाबाद। सोमवार सुबह से हुई मूसलाधार बारिश ने स्मार्ट सिटी मुरादाबाद को तालाब के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस बारिश से नगर निगम की नाला सफाई और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की पोल खोल कर रख दी। नतीजा यह हुआ कि महानगर की 'यादातर सड़के तालाब में तब्दील हो गईं। वहीं वीआईपी कॉलोनी में शुमार रामगंगा विहार की रंगोली कॉलोनी अवंतिका में भीषण जल भराव का नजारा देखने को मिला। हालात इतने 'यादा खराब रहे कि नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल को बारिश के बीच सड़कों पर उतरना पड़ा। उन्होंने अपनी निगरानी में पम्पों से पानी निकलवाया। बारिश के बीच सबसे 'यादा खराब हाल लाइन पार की कॉलोनी का दिखाई दिया, यहां विकास नगर की सड़कों पर डेढ़ से दो-दो फीट पानी जमा हुआ था। यहां रहने वाले तमाम लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया इससे कीमती सामान भी भीगने से खराब हो गया। शहर के अंदरुनी कॉलोनी का भी बुरा हाल नजर आया। झब्बू का नाला, किसरौल, लाल मस्जिद, रेती स्ट्रीट, बुद्ध बाजार, पीरगेब, वारसी नगर, करुला, जयंतीपुर, मियां कॉलोनी में भी भयंकर जल भराव का सामना स्थानी लोगों को करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के तहत विकास के नाम पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। लोगों ने मनमाना हाउस टैक्स और वाटर टैक्स वसूला जा रहा है, मगर महानगर के ड्रेनेज प्लान पर किसी का ध्यान नहीं है पिछले दिनों मुरादाबाद दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जल भराव को लेकर ड्रेनेज प्लान भेजने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए थे।

कई इलाकों में घरों तक में घुसा पानी, सड़कों पर उतरे नगर आयुक्त

नो हेल्मेट नो फ्यूल" रणनीति पर जनपद में सख्ती से होगा अमल

बहराइच।

हेल्मेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर प्रभावी अंकुश तथा सड़क सुरक्षा के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह के निर्देश पर जनपद में ''नो हेल्मेट, नो फ्यूल'' की रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के उद्देश्य से जनपद में एक से 30 सितम्बर 2025 तक संचालित होने वाले अभियान के प्रथम दिन एआरटीओ (प्रवर्तन) ओ.पी. सिंह ने इण्डियन ऑयल डिगिहा पेट्रोल पम्प, इण्डियन ऑयल चोपड़ा पेट्रोल पम्प, माँ भगवती पेट्रोल पम्प पानी टंकी एवं केडीसी के निकट स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प पर जाकर उपस्थित लोगों को दो पहिया वाहन चलाते समय हेल्मेट का प्रयोग करने हेतु जागरूक किया गया। पेट्रोल पम्पों के निरीक्षण के दौरान एआरटीओ श्री सिंह ने आमजन को बताया कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-129 एवं उ.प्र. मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 201 के अनुसार सभी मोटर साईकिल चालकों एवं सवारियों के लिये भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है।उन्होंने बताया कि प्राविधानों का उल्लंघन करने पर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है। जिसमें जुर्माना का प्राविधान भी है। श्री सिंह ने पेट्रोल पम्प संचालकों से कहा कि ''नो हेल्मेट, नो फ्यूल'' की रणनीति पर अमल करें तथा हेल्मेट के बगैर किसी व्यक्ति को पेट्रोल कदापि न दें। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में डीएम व एसपी द्वारा समस्त पेट्रोलियम कम्पनी के विक्रय अधिकारियों एवं पेट्रोल पम्प के प्रोपराइटर्स को 01 से 30 सितम्बर 2025 तक ''नो हेल्मेट, नो फ्यूल'' की रणनीति को कड़ाई के साथ लागू करें। जनपद बहराइच के सभी पेट्रोल पम्प द्वारा दो पहिया वाहन चालकों को बिना हेल्मेट के पेट्रोल का विक्रय नही किया जायेगा। बैठक के माध्यम से यह भी निर्देश दिये गये हैं कि 01 से 30 सितम्बर 2025 तक ''नो हेल्मेट, नो फ्यूल'' की रणनीति के प्रचार-प्रसार के लिये सभी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थानो, पेट्रोल पम्पों, तहसील मुख्यालयों, स्कूल, कालेज, सामुदायिक केन्द्रों व अन्य महत्वपूर्ण स्थनों पर होर्डिंग्स, बैनर व पोस्टर के माध्यम से तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म से भी ''नो हेल्मेट, नो फ्यूल'' की रणनीति का प्रचार-प्रसार किया जाय ताकि आमजनमानस को अभियान की जानकारी हो सके।

01 से 30 जुलाई तक जनपद में संचालित होगा अभियान

बहराइच में आयोजित कवि सम्मेलन व मुशायरा में दो दर्जन रचनाकारों, लेखकों, कवियों व शायरों को किया गया सम्मानित

बहराइच ।

युवा शायरों व कवियों को उनकी साहित्यक गुणों के आधार पर साहित्य जगत में पहचान देने और उनके टैलेंट को निखारने में आज बहुत नाम मात्र लोग बचे हुए या उनकी संस्थायें शेष हैं।फख्र ए हिंदुस्तान संस्था उन में से एक है। बहराइच में आज फ़ख्र ए हिंदुस्तान लखनऊ ने अवध वाटिका साहित्य संस्थान बहराइच के सहयोग से जो साहित्यक कार्यक्रम आयोजित किया है और जिस प्रकार से जनपद के एक से बढ़कर एक रचनाकारों ने अपनी रचनायें प्रस्तुत की है वह ऐतिहासिक है। उक्त विचार आज सेनानी भवन सभागार कलेक्ट्रेट परिसर बहराइच में फ़ख्र ए हिंदुस्तान संस्था लखनऊ के कवि सम्मेलन मुशायरा व अदब के जुगनू सम्मान 2025 समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि महामंत्री बहराइच ईंट निर्माता संघ व सुप्रसिद्ध समाज सेवी मोहम्मद अब्दुल्ला ने कही। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि इरशाद हुसैन राही लखनऊ ने बहराइच के साहित्यकारों पर विशेष प्रकाश डालते हुए कहा कि बहराइच ने हिन्दी- उर्दू साहित्य में बहुत सराहनीय योगदान दिया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रमेश चंद्र मिश्रा ने फख्र ए हिंदुस्तान की साहित्यक सेवाओं पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आज जिले के दो दर्जन साहित्यकारों को सम्मानित कर बहराइच का मान बढ़ाया है। कार्यक्रम के कन्वीनर देशराज देसाई एवं ऑर्गेनाइजर व व्यवस्थापक आरिफ अल्वी फ़ख्र ए हिंदुस्तान लखनऊ की जानिब से मुख्य अतिथि मोहम्मद अब्दुल्ला, अध्यक्षता कर रहे रमेशचंद्र मिश्र , विशिष्ट अतिथि इरशाद हुसैन राही व डाक्टर तैयब हुसैन व डाक्टर अब्दुल्ला के हाथों अदब के जुगनू सम्मान 2025 खुंस सिद्दीकी, पी के प्रचण्ड बहराइच, डॉक्टर अब्दुल सुब्हान शाद बलरामपुरी, फ़ौक बहराइची,डॉक्टर सगीर अहमद सिद्दीकी बहराइच, मेराज शिवपुरी ,कलीम अहमद खां बहराइच, तारिक हाशिम बहराइच ,उमर खान नानपारवी, अज़्म गोंडवी ,अहमद रजा प्यारेपूरी, महीप चंद कनौजिया, विनोद कश्यप,वसीम जौहर नगरौरवी ,तिलक राम अजनबी एडवोकेट ,किशोरी लाल अनाम एडवोकेट ,शाहनवाज खान नवाज बहराइची, शैलेंद्र सागर बहराइच, इलियास चिश्ती लखीमपुर-खीरी, नीलेंद्र राणा बहराइच को माल्यार्पण कर मेमोंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लखीमपुर-खीरी से पधारे युवा शायर इलियास चिश्ती के शानदार संचालन में मुशायरा कवि सम्मेलन भी सम्पन्न हुआ।जिसमें सम्मानित साहित्यकारों के अलावा जगदीश सिंह प्राचार्य, नसीम बहराइची, विनोद कुमार पांडेय ने काव्य पाठ किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोहम्मद अब्दुल्ला महामंत्री ईंट निर्माता संघ बहराइच और कार्यक्रम के अध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्र महामंत्री सेनानी कल्याण परिषद बहराइच एवं विशिष्ट अतिथि रूबरू फाउंडेशन के अध्यक्ष इरशाद हुसैन राही लखनऊ को भी फ़ख्र ए हिंदुस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दरगाह शरीफ प्रबंध कमेटी के सदस्य बच्चे भारती ,शुएब इकबाल एडवोकेट, शफीक अहमद बाग़बान, कामरान सिद्दीकी, रुस्तम अली शैदा, हामिद अली समेत सैकड़ों श्राताओं ने की शिरकत ने कार्यक्रम को सफल बनाया।

त्रयोदश गणेश महोत्सव का हवन और शोभायात्रा के साथ हुआ समापन

मुरादाबाद।

नवीन नगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पाँच दिवसीय त्रयोदश गणेश महोत्सव का समापन हवन एवं गणेश विसर्जन के साथ हुआ। सुबह विशेष हवन एवं पूजन-अर्चन का आयोजन किया गया, जिसमें पं. दयानंद जोशी के मंत्रों चारण के बीच नमिता सक्सैना और सूरज सक्सैना ने विधि-विधान से पूजन सम्पन्न किया। हवन में क्षेत्रवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पूरे वातावरण में भक्ति और आस्था की छटा बिखरी रही। हवन के उपरांत गणपति बप्पा की शोभायात्रा बड़े हर्षोल्लास के साथ मंदिर प्रांगण से निकली। इस यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भजन-कीर्तन, ढोल-नगाड़ों और गणपति बप्पा मोरयाञ अगले बरस तू जल्दी आ, के गगनभेदी जयकारों से वातावरण गूँज उठा। क्षेत्रीय नागरिक, महिलाएँ और बच्चे सभी यात्रा में शामिल हुए और बप्पा को विदाई दी। इस दौरान मनोज सक्सैना, विकास, आशीष सक्सैना, वरुण, अर्जुन दुबे, अनमोल सक्सैना, शैली अरोड़ा, आदि लोग उपस्थित रहे। प्रतिमा को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ रामगंगा नदी तक ले जाया गया, जहाँ विधिपूर्वक जलविहार एवं विसर्जन सम्पन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने गणपति से पुनः अगले वर्ष पुनः पधारने की प्रार्थना करते हुए बप्पा को भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य लोग तथा अनेक श्रद्धालु जिनमें पार्षद पंकज शर्मा, मंजू लता, आकृति सिन्हा, पूनम अरोरा, रेखा शर्मा, मीना सक्सैना, सीमा शर्मा, सोनल सक्सैना, अभिव्यक्ति सिन्हा, ऊषा, सीमा गौड़, सुषमा सिंह, आकांक्षा दीप, कुसुम थरेजा, अर्चना सक्सैना, शशि किरण सहित अन्य भक्तजन की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। पूरे पाँच दिनों तक चले इस महोत्सव ने क्षेत्रवासियों को भक्ति, उत्साह और एकता से जोड़कर एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान किया। वहीं बच्चों में दिया, परी, खुशी, आशी, भूमि, ईशान, अक्षत, ध्रुव गौड़, कार्तिकेय शर्मा, आदि भी मौजूद रहे।

मुफ्ती नदीम ने शरिया लॉ में हासिल किये 95 प्रतिशत अंक

मिस्त्र काहिरा की अल अज़हर यूनिवर्सिटी में हासिल की तालीम

मुरादाबाद। मिस्त्र (काहिरा) की अल - अज़हर यूनिवर्सिटी में तीन साल से पढ़ रहे मुफ्ती मोहम्मद नदीम अज़हरी ने शरिया लॉ के सालाना इम्तेहान मे 95 प्रतिशत नम्बर लाकर भारत का नाम रोशन किया। इस मौके पर कुन्दरकी और आस पास के लोगो में मुफ्ती मौहम्मद नदीम अज़हरी को मुबारकबाद पेश की , और उनके वालिद कारी अब्दुल वकील (नाजिम - ए - आला दारुल उलूम रजा ए . मुस्तफा) व सभी घर वालो को मुबारकबाद दी इस मौके पर सय्यद् नासिर मियां , कारी वसीम मियां , मुफ्ती मुजफ्फर मुफ्ती मुस्लिम , मुफ्ती साजिद , मौलाना हबीब , कारी मुनाजिर कारी मुहफूज , कारी रफीक अशरफ , और वसीम व शुऐब रजा मे मुबारकबाद पेश पेश की ।

जमियत-ए-उलेमा शहर के नये अध्यक्ष बने मौलाना मोहम्मद ताहिर

सर्व सम्मति से हुआ चुनाव, मौलाना मुजम्मिल हुसैन बने महासचिव

मुरादाबाद।

जमियत-ए-उलेमा शहर की एक चुनावी सभा पीरगैब स्थित शादी हाल में महानगर अध्यक्ष हाफिज आलम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सभा का संचालन महा सचिव मौलाना मुजम्मिल हुसैन ने किया। सभा की शुरुआत कुराने पाक की तिलावत व नाते नबी से हुई। महा सचिव ने तीन साल क्रम पूरा होने पर रिपोर्ट पेश की, सभी सदस्यों ने इसकी पुष्टि की। रिपोर्ट के बाद नया चुनाव का एलान हुआ, यह एलान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महा सचिव कारी यामीन व सचिव शकील अहमद ने किया। उन्होंने चुनाव से पहले जमियत-ए-उलेमा हिन्द के नियम पढ़कर सुनाये, फिर उनहोंने नए ट्रंप 2025 से 2027 के चुनाव संपन्न कराये। उन्होंने नये अध्यक्ष के चुनाव के लिए सदस्यों से नाम लेने की अपील की। सदस्य हाजी तय्यब ने मौलाना मोहम्मद ताहिर (मोहतमिम मदरसा जामेउल हुदा) का नाम पेश किया, जिसे सभी मौजूद सदस्यों ने सर्वसम्मिति से मंजूर कर लिया। मौलाना मोहम्मद ताहिर के मुकाबले किसी उम्मीदवार ने अपना नाम पेश नहीं किया। चुनाव अधिकारी मौलाना यामीन ने शहर का नया अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद ताहिर को घोषित किया। इसी तरह उपाध्यक्ष पद के लिये कारी नजीबुर रहमान, हाफिज मोहम्मद आलम, कारी मोहम्मद इब्राहीम और मौलाना मोहम्मद अख्तर के नामी पर रजामन्दी हुई। महा सचिव पद के लिए मौलाना मुजम्मिल व कारी नफीसुर रहमान का नाम पेश हुआ। इसके बाद कारी नफीसुर रहमान ने अपना नाम वापस ले लिया, चुनाव अधिकारी मौलाना मोहम्मद यामीन ने महा सचिव पद के लिए मौलाना मुजम्मिल हुसैन के नाम का एलान किया। कोषाध्यक्ष के लिए हाजी नसीम सिद्दीकी का नाम पेश हुआ, जिसे सर्वसम्मिति से मंजूर कर लिया गया।

शहर जमियत-ए-उलेमा का पूरा चुनाव शांति पूर्वक हुआ।

नवनियुक्त अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद ताहिर ने सभी सदस्यों व मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। चुनावी सभा की सरपरस्ती मुफ्ती अबू बकर ने की।

इस सभा में मौलाना अतीक अहमद, हाफिज इश्रतुल्लाह, मुफ्ती मोहम्मद फारूक, मौलाना मोहम्मद उस्मान, मुफ्ती अब्दुल हक, (रसूलपुरी), कारी नाफीसुर रहमान, मौलाना अबुजर, मौलाना एहरार आलम, मुफ्ती जलालुद्दीन, डॉक्टर निजामुद्दीन, रिजवान कुरैशी, मुफ्ती मोहम्मद तय्यब, मौलाना मोहम्मद याहया, मौलाना अब्दुल्लाह, हाजी निजामुद्दीन, मोहम्मद जुनैद आदि मौजूद रहे।

विपक्ष के प्रत्याशी ने सभी दलों के सांसदों को लिखा पत्र, चुनाव आयोग पर की गंभीर टिप्पणी

नई दिल्ली।
उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्षी खेमे- इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी सेवानिवृत्त जस्टिस रेड्डी ने सभी दलों के सांसदों को पत्र लिखा है। बता दें कि रेड्डी का मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन से है। दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में समीकरणों को मजबूत करने लेकर सत्ताधारी गुट के साथ-साथ विपक्षी दलों को भी एकजुट रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच रेड्डी का सांसदों को पत्र लिखना चर्चा में है।

अगर दोनों प्रत्याशी चाहें तो चुनाव से पहले बहस हो सकती है

आगामी 9 सितंबर को होने वाले मतदान से पहले इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने हैदराबाद में कहा, मेरे प्रतिद्वंद्वी बोल नहीं रहे हैं। अगर दोनों उम्मीदवार बोलें तो बहस हो सकती है। रेड्डी ने कहा, मैं विपक्षी दलों का उम्मीदवार हूं, मुझे आप जैसी गैर इंडिया ब्लॉक पार्टियों से समर्थन मिला है।

उन्होंने कहा, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव उनके जीवन में संविधान के साथ लंबी यात्रा का एक हिस्सा है। उन्होंने भरोसा जताया कि 2025 का चुनाव भारत के हालिया इतिहास में लड़े गए सबसे निष्पक्ष, प्रतिष्ठित और मर्यादित चुनावों में से एक होगा।

संविधान का काम शक्तियों को सीमित करना

हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, हमारा राय बहुसंख्यकवादी नहीं है। संविधान किसी को शक्ति नहीं देता, उसका काम शक्ति को सीमित करना है। उन्होंने चुनाव आयोग के कामकाज पर भी टिप्पणी की। रेड्डी ने कहा, संविधान के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में कमी है।

विपक्ष का दांव- न्यायप्रिय छवि वाले रेड्डी

79 वर्षीय रिटायर्ड जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट से जुलाई 2011 में सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले वे आंध्र प्रदेश, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। उन्होंने अपने न्यायिक करियर में कई अहम फैसले दिए, जिसमें काला धन मामले में केंद्र सरकार की ढिलाई की आलोचना, छत्तीसगढ़ सरकार की सलवा जुडूम नीति को असांविधानिक ठहराना और काले धन की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने जैसे आदेश प्रमुख हैं। कांग्रेस और विपक्षी दल मानते हैं कि रेड्डी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के सतत व साहसी समर्थक हैं। तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण कराने वाली समिति का नेतृत्व करने को लेकर भी रेड्डी चर्चा में रहे।

सत्ताधारी दल के प्रत्याशी को पर्याप्त समर्थन का दावा, एक दिन पहले पीएम देंगे रात्रिभोज

गौरतलब है कि रेड्डी के पत्र लिखने से एक दिन पहले आई खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सभी सांसदों को रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया है। एनडीए के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि इस तरह का आयोजन गठबंधन की एकता को मजबूत करने में हमेशा उपयोगी साबित होता है। उन्होंने कहा, यद्यपि हमारे उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के सभी सहयोगियों का पूर्ण समर्थन हासिल है, यह रात्रिभोज मतदान के दौरान सांसदों के बीच समन्वय और एकता सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

बिहार मतदाता सूची को लेकर 1 सितंबर के बाद भी स्वीकार होंगी आपत्तियां, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

नई दिल्ली।
उच्चतम न्यायालय ने बिहार में मसौदा मतदाता सूची तैयार करने के लिए पूर्व निर्धारित समय सीमा (1 सितंबर) के बाद भी राय के निवासियों के दावे या आपत्तियां स्वीकार करने की चुनाव आयोग को सोमवार अनुमति दे दी। इस साल जून में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बिहार में मसौदा मतदाता सूची तैयार करने का शुरू किया गया। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अनुमति देते हुए चुनाव आयोग को इस दलील पर गौर किया कि नामांकन (इस साल निर्धारित विधानसभा चुनाव) की अंतिम तिथि से पहले दायर किए गए सभी दावों या आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल और एआईएमआईएम द्वारा दावे और आपत्तियां दायर करने की समय सीमा दो सप्ताह बढ़ाने के लिए दायर आवेदनों पर विचार करते हुए यह अनुमति दी। शीर्ष अदालत के समक्ष चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी कहा कि दावे या आपत्तियां एक सितंबर की समय सीमा के बाद भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ठन पर विचार किया जाएगा।

नामांकन की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी प्रक्रिया

अधिवक्ता द्विवेदी ने आश्वासन दिया कि यह प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी और सभी शामिल या हटाए गए नामों को जांच प्रताल के बाद अंतिम सूची में शामिल किया जाएगा। न्यायालय ने आपत्तियां दर्ज कराने में संबंधित व्यक्तियों की सहायता के लिए अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों की तैनाती का भी निर्देश दिया। साथ ही, राजनीतिक दलों से भी इस प्रक्रिया में सक्रिय होने को कहा। पीठ के समक्ष द्विवेदी ने कहा कि 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 फीसदी ने अपने फॉर्म दाखिल कर दिए हैं। मसौदे से बाहर किए गए 65 लाख मतदाताओं में से, केवल 33,326 लोगों और 25 दलों के माध्यम से दावे प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हटाए गए नामों के लिए 1,34,738 आपत्तियां दायर की गई हैं।

शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त को दिया था ये आदेश

अधिवक्ता ने कहा कि यह अजीब है कि राजनीतिक दल मसौदा सूची से मतदाताओं को हटाने की मांग करते हुए आपत्तियां दायर कर रहे हैं, न कि शामिल करने के लिए कोई दावा। शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त को आदेश दिया था कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जिन लोगों को मतदाता सूची के प्रारूप से बाहर रखा गया है, वे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्हें व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं है। राज्यसभा सांसद मनोज झा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), पोयूसीएल, स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव, तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा और बिहार के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने समेत अन्य ने याचिकाएं दायर की थीं।

डीयू कॉलेजों को खेल के लिए 5 फीसदी सीटें आरक्षित करने का आदेश, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली । सीबीएसई के लॉन टेनिस में राष्ट्रीय स्तर के स्वर्ण पदक विजेता द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से संबद्ध सभी कॉलेजों को भविष्य में प्रवेश के दौरान पाठ्येतर गतिविधियों (ईसीए) और खेल कोटा के लिए अनिवार्य 5फीसदी आरक्षण का पालन करना होगा। यह मामला नाबालिग अदिति रावत द्वारा दायर किया गया था, जिसका प्रतिनिधित्व उसकी माँ अनीता रावत ने किया था। वह शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए हिंदू कॉलेज में खेल कोटे के तहत सीट मांग रही थी। रावत के वकील, जितेंद्र गुप्ता, भरत रावत और आशीष मिश्रा ने तर्क दिया कि डीयू की प्रवेश नीति के अनुसार, प्रत्येक कॉलेज में कुल सीटों में से 5फीसदी सीटें ईसीए/खेल के लिए आरक्षित होना अनिवार्य है, जबकि हिंदू कॉलेज ने स्वीकृत 956 सीटों में से ईसीए और खेल के लिए केवल 10-10 सीटें आवंटित की हैं - जो आवश्यक 47 सीटों से बहुत कम है। हिंदू कॉलेज ने तर्क दिया कि डीयू के सूचना बुलेटिन में उल्लिखित कोटा अनिवार्य नहीं था। हालांकि, दिल्ली विश्वविद्यालय ने अदालत में पेश किए गए एक हलफनामे में पुष्टि की कि कॉलेज अपने स्वीकृत प्रवेशों का 5त ईसीए और खेल प्रवेश के लिए आरक्षित रखने के लिए बाध्य है। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने कहा कि विश्वविद्यालय के हलफनामे में कोई अस्पष्टता नहीं है; कोटा

एससीओ सम्मेलन में पीएम मोदी का कड़ा संदेश, कहा-

आतंकवाद पर दोहरा रवैया अब नहीं चलेगा

नेशनल डेस्क ।
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के 25वें शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर बेहद स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाया। चीन के तियानजिन में आयोजित इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आतंकवाद आज केवल किसी एक देश के लिए खतरा नहीं बल्कि पूरे विश्व, खासकर मानवता के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। इस सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का आतंकवाद के समर्थन को लेकर कुछ देशों पर सीधा सवाल उठाना और उसे अस्वीकार्य बताना काफी अहम माना जा रहा है।

पहलगाम हमले का जिक्र और भारत का दर्द

प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत पिछले चार दशकों से आतंकवाद के जख्म झेल रहा है। उन्होंने कहा, हाल ही में, हमने पहलगाम में आतंकवाद का सबसे बुरा रूप देखा। मैं इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े मित्र देशों का आभार व्यक्त करता हूं। इस बयान के माध्यम से प्रधानमंत्री ने भारत की पीड़ा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उजागर किया और यह बताया कि आतंकवाद का असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है।

आतंकवाद पर दोहरा मापदंड स्वीकार नहीं

अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी देश का नाम लिए कहा कि कुछ देश अब भी आतंकवाद का खुला समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने यह सवाल उठाया कि क्या ऐसा रवैया अब और सहन किया जा सकता है? हमें स्पष्ट रूप से और एकमत से कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं है। यह हमला मानवता में विश्वास रखने वाले प्रत्येक देश और व्यक्ति के लिए एक खुली चुनौती थी। उनका यह बयान साफ तौर पर पाकिस्तान की ओर इशारा करता है जो लंबे समय से भारत पर आतंकी संगठनों को पनाह देने के आरोपों से घिरा रहा है।

एससीओ में भारत की भूमिका

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एससीओ में भारत की सकारात्मक भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भारत की नीति तीन मूल स्तंभों पर आधारित है-
एस - सुरक्षा, सी - संपर्क और ओ - अवसर। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा दिया है और आगे भी इसी दिशा में काम करता रहेगा।

आरएटीएस के तहत भारत की अगुवाई

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत ने एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी ढांचे के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया, भारत ने संयुक्त सूचना अभियान का नेतृत्व करके अंत-कायदा और उससे जुड़े संगठनों से लड़ाई में अहम योगदान दिया है। साथ ही, भारत ने आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ भी आवाज उठाई है। इसका उद्देश्य सिर्फ आतंकी घटनाओं को रोकना नहीं, बल्कि उनकी जड़ों को खत्म करना है – यानी उनके वित्तीय स्रोतों को भी बंद करना।

आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता जरूरी

अपने भाषण के अंत में प्रधानमंत्री ने सभी एससीओ देशों से अपील की कि आतंकवाद को किसी भी तरह के रंग, धर्म या राजनीति से न जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि मानवता के खिलाफ जो भी खड़ा है, उसके खिलाफ एकजुट होना हम सभी का कर्तव्य है। उनका यह संदेश वैश्विक आतंकवाद से लड़ने की दिशा में एक बार फिर भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मराठा आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, हुआ सभी शर्तों का उल्लंघन, एक्शन ले सरकार

मुंबई । मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन कर रहे मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे की बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी आलोचना की है। हाईकोर्ट ने कहा कि जारंगे के नेतृत्व वाला विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं था और इसमें उन सभी शर्तों का उल्लंघन किया गया था जिनके तहत उन्हें अनुमति दी गई थी। अदालत ने कहा कि पूरा शहर ठप्प से गया था और दक्षिण मुंबई के प्रमुख स्थानों को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया था। न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की एक विशेष पीठ ने आरक्षण विरोध के खिलाफ एमी फाउंडेशन द्वारा दायर मामले की विशेष सुनवाई की। जारंगे ने मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर शुक्रवार को अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने मराठों को कुनबी (अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल एक कृषक जाति) के रूप में मान्यता देने की मांग की, जिससे वे सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के पात्र हो सकें। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनकी मांग संवैधानिक रूप से वैध है, तथा कहा कि सरकारी रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि कुनबी और मराठा एक ही जाति के हैं। जरांगे ने चेतावनी दी कि अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनकी मांगें नहीं मानीं, तो 5 करोड़ से ज्यादा मराठा मुंबई आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मराठा मुंबई आने का इंतजार कर रहे हैं। वे सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अगर फडणवीस समुदाय की मांगें नहीं मानते, तो 5 करोड़ से ज्यादा मराठा मुंबई आ जाएंगे। आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समुदाय के सैकड़ों लोग छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) और दक्षिण मुंबई के अन्य इलाकों में जमा हो गए, जिससे यातायात जाम हो गया और यात्रियों को परेशानी हुई। इसके जवाब में, पुलिस ने सीएसएमटी क्षेत्र की ओर जाने वाले वाहनों का मार्ग बदल दिया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) ने सीएसएमटी जाने वाली कई बस सेवाओं को निलंबित, परिवर्तित या छोटा कर दिया।

जम्मू में बाढ़ से मची तबाही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का किया आकलन

श्रीनगर। जम्मू में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजभवन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद, जिसमें जिम्मा के नेता सुनील शर्मा भी मौजूद थे, शाह जिले के सबसे अधिक प्रभावित गांव मंगूचक सहित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सिन्हा और उमर अब्दुल्ला के साथ, शाह विक्रम चौक के पास तवी पुल पर रुके और नदी के किनारे हुए नुकसान का निरीक्षण किया। वह बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों का आकलन करने के लिए रविवार रात जम्मू पहुंचे थे। 14 अगस्त से किश्तवाड़, कठुआ, रियासी और रामबन जिलों में बादल फटने, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 130 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 33 लापता हैं। 26-27 अगस्त के दौरान रिकॉर्ड बारिश के कारण जम्मू और अन्य मैदानी इलाकों के निचले इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। मृतकों में 34 तीर्थयात्री शामिल हैं, जो 26 अगस्त को माता वैष्णो देवी मंदिर जाते समय हुए भूस्खलन की चपेट में आ गए थे। खराब मौसम और मार्ग पर सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण वैष्णो देवी यात्रा सोमवार को सातवें दिन भी स्थगित रही। कटरा स्थित आधार शिविर त्रीकूटा पड़ा रहा और कुछ ही तीर्थयात्री यात्रा बहाल होने का इंतजार कर रहे थे। सोमवार सुबह मौसम में थोड़ा सुधार देखा गया, जिससे यात्रा जल्द शुरू होने की उम्मीद जगी है। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और संबंधित एजेंसियों से मंजूरी मिलने के बाद ही आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।

पूर्वी अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही; गांव के गांव बर्बाद, कम से कम 800 लोगों की मौत, 2500 घायल

काबुल । पूर्वी अफगानिस्तान में आए एक शक्तिशाली भूकंप में लगभग 800 लोगों की मौत हो गई। अब तक 2,500 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। रविवार देर रात 6.0 तीव्रता का भूकंप नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर के पास कुनार प्रांत के कई कस्बों में आया, जिससे भारी नुकसान हुआ।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक, रात 11:47 बजे आए भूकंप का केंद्र नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व में था। इसकी गहराई महज 8 किलोमीटर थी। कम तीव्रता वाले भूकंप ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद भी इलाके में कई झटके आए। सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर प्रसारित वीडियो फुटेज में बचावकर्मी घायल लोगों को ढही हुई इमारतों से स्ट्रेचर पर उठाकर हेलीकॉप्टरों में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कई लोग अपने हाथों से मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं।

तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मृतकों की संख्या बढ़कर 800 हो गई है। 2,500 लोग घायल हुए हैं। ज्यादातर लोग कुनार प्रांत में हताहत हुए हैं।

लगभग पूरा गांव ही तबाह हो गया

कुनार के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक नूरगल जिले के एक निवासी ने बताया कि लगभग पूरा गांव ही तबाह हो गया है। बचे मलबे के नीचे हैं। बुजुर्ग मलबे के नीचे हैं। खून मलबे के नीचे है। हमें मदद की जरूरत है। हमें लोगों की जरूरत है, जो यहां आकर हमारी मदद करें। अहद हम दबे हुए लोगों को बाहर निकालें। कोई भी ऐसा नहीं है, जो आकर मलबे के नीचे से शवों को निकाल सके।

तृणमूल के विरोध-प्रदर्शन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अनैतिक और अलोकतांत्रिक; सीएम ममता ने लगाए गंभीर आरोप

बेबवार्ता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल- तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) राज्य के प्रवासियों का उत्पीड़न होने के विरोध में आवाज उठा रही है। कोलकाता में प्रदर्शन के लिए टीएमसी का मंच तैयार किया जा रहा था, जिसे सेना ने कथित तौर पर ध्वस्त कर दिया। सीएम ममता बनर्जी ने सेना के इस कदम को अनैतिक और अलोकतांत्रिक करार दिया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बंगाल प्रवासियों के उत्पीड़न के विरोध में बनाए गए टीएमसी के मंच को सेना द्वारा ध्वस्त करने के पीछे भाजपा का हाथ है। विपक्षी दल प्रतिशोध की राजनीति कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, कोलकाता में टीएमसी के मंच को हटाने से पहले सेना को कोलकाता पुलिस से परामर्श करना चाहिए था। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा, मैं सेना को दोष नहीं देती, बस उनसे अपील करती हूं कि वे तटस्थ रहें और भाजपा के हाथों की कठपुतली बनने से बचें।

निजी बस ने ट्रेलर ट्रक को मारी टक्कर, चार लोगों की मौत

तेलंगाना ।तेलंगाना के महबूबनगर जिले में सोमवार तड़के एक निजी बस ने ट्रेलर ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार चार लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना अठकल पुलिस थाना क्षेत्र में आधी रात के बाद करीब 2.15 बजे हुई। एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पांच अन्य लोग घायल हो गए।

उफनती यमुना से दिल्ली में बाढ़ का संकट, मंत्री प्रवेश वर्मा का आश्वासन- सरकार पूरी तरह तैयार

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हथिनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। इस पर दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि अधिकारियों के अनुसार, नदी का जलस्तर आज देर रात खतरे के निशान को पार कर सकता है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली सरकार ने स्थिति पर कड़ी नजर रखी है और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

दिल्ली सरकार हाई अलर्ट पर है और टीमें जमीन पर सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। सरकार हर दिल्लीवासी की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।

आसपास के इलाकों को कराया गया खाली

बता दें, पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इस कारण यमुना नदी में यह पानी 48 से 60 घंटे में दिल्ली में पहुंच जाएगा। यदि पानी का बहाव और तेज होता है तो यह 24 घंटे में दिल्ली में प्रवेश कर जाएगा, जिससे बड़ी तबाही ला सकता है। यमुना नदी के किनारे वाले गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार ने यहां रहनेवाले लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया है।

नो हेलमेट, नो पेट्रोल को लेकर योगी सरकार ने फिर शुरू की सख्ती

लखनऊ।
नो हेलमेट, नो पेट्रोल के आदेश का अनुपालन कराने के लिए सरकार ने पुन सख्ती शुरू कर दी है। 30 सितंबर तक अभियान चलाकर प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी हेलमेट की अनिवार्यता के प्रति चालकों को जागरूक करेंगे। व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पंप स्वामियों से भी सहयोग की अपील की गई है। प्रदेश सरकार ने सात माह पूर्व नो हेलमेट, नो पेट्रोल का नियम लागू किया था। बावजूद पंपों पर आदेश चस्पा कर लोगों से भी सहयोग मांगा था। व्यवस्था का पालन कराने की जिम्मेदारी अधिकारियों पर थी, लेकिन ढुलमुल नीति के कारण व्यवस्था दम तोड़ गई। अब शासन ने पुन 30 सितंबर तक अभियान चलाकर लोगों को नियम के प्रति गंभीरता दिखाने को कहा गया है। सोमवार को एआरटीओ शिवम यादव के साथ यातायात प्रभारी

प्रदीप सेंगर ने नगर के अलग-अलग पंपों पर पहुंचकर चालकों को आदेश की जानकारी दी। पहले दिन किसी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई तो नहीं की गई, लेकिन स्पष्ट कर दिया है कि बिना हेलमेट के अब डीजल अथवा पेट्रोल नहीं मिल सकेगा। निरंतर नियमों की अनदेखी करने वाले 45 चालकों के सामान्य चालान जरूर कर उन्हें दोबारा नियम का उल्लंघन न करने का संदेश दिया गया। एआरटीओ का कहना है कि इस पूरे अभियान में परिवहन विभाग, यातायात विभाग, जिला पूर्ति अधिकारी एवं स्थानीय पुलिस को संयुक्त रूप से कार्रवाई करनी होगी। व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए सभी पंप स्वामियों से सहयोग की अपील की गई है।

हेलमेट के आदान-प्रदान पर दोगुना जुर्माना

पिछली बार चले अभियान में शातिर लोगों ने इस आदेश को कमाई का माध्यम बना लिया था। पंप पर ही कर्मचारियों अथवा अन्य लोगों द्वारा हेलमेट उपलब्ध कराए जाते थे। बिना हेलमेट आने वालों को 10 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लेकर उन्हें हेलमेट दिया जाता था और पेट्रोल भरवाने के बाद चालक वापस कर जाते थे। इस बार यदि ऐसे प्रकरण सामने आते हैं तो चालक और हेलमेट उपलब्ध कराने वालों के विरुद्ध दोगुने जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।